यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/28/2018 **दिनांक :** 21.03.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

यूएफबीयू द्वारा अपनी माँगों को लेकर संसद पर धरना

यूएफबीयू के आह्वान पर आज दिनांक 21.03.2018 को संसद के सम्मुख यूएफबीयू की घटक यूनियनों ने पूर्णदिवसीय धरना दिया। इस धरने का उद्देश्य मुख्यतः अपनी माँगों जैसे वेतन पुनरीक्षण, पंजाब नैशनल बैंक में हाल में हुई धोखाधड़ी और उस सन्दर्भ में छोटे स्तर के कर्मचारियों को उत्पीड़ित किया जाना तथा उच्च प्रबन्धन को खुली छूट देना आदि मामलों को प्रदर्शित किया गया। इसी सन्दर्भ में यूएफबीयू के घटक दलों के नेता वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली से मिले और उन्हें निम्नलिखित मामलों में स्मरण पत्र दिये :–

1. **बैंकों में वेतन पुनरीक्षण**
2. **पंजाब नैशनल बैंक में हाल में हुई धोखाधड़ी**
3. **बैंकों में कर्मचारी निदेशकों तथा अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति में अनुचित देरी**
4. **बैंकों में कर्मचारी कल्याण योजनाओं के लिए निधि का आवंटन**

हम इन प्रतिवेदनों का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पूर्व धरना स्थल पर यूएफबीयू के नेतृत्व ने अपने विचार रखे साथ ही सांसद डी. राजा तपन सेन आदि ने भी अपने विचारों से अवगत कराया।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रति

माननीय श्री अरूण जेटली
वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

आदरणीय महोदय,

विषय : बैंकों में वेतन पुनरीक्षण

आपको ज्ञात ही है कि बैंकों में वेतन पुनरीक्षण 1.11.2017 से देय है क्योंकि पिछला समझौता 31.10.2017 को समाप्त हो चुका है। वित्त मंत्रालय ने वेतन पुनरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैंकों तथा इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को बार–बार स्मरण कराया है।

भले ही इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने वेतन पुनरीक्षण और सेवाशर्तों में सुधार के लिए हमारे द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर यूनियनों के साथ विचार–विमर्श प्रारम्भ कर दिया है, कोई ठोस सुधार संभव नहीं रहा है क्योंकि आईबीए ने अभी तक वेतन वृद्धि पर अपना आरम्भिक प्रस्ताव भी नहीं किया है। वार्ता के कई दौर हो चुके हैं किन्तु आईबीए अपना प्रस्ताव करने के लिए आगे नहीं आई है। वास्तव में, पिछले चार या पांच महीनों से विचार–विमर्श तक नहीं हुआ है।

इस प्रकार वार्ता लगभग रूक गई है और वार्ता और समझौते में देरी से कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच असंतोष पैदा हो रहा है।

आपको ज्ञात ही होगा कि अधिकारियों के संबंध में, 1979 से, सरकार के इशारे पर, अधिकारियों के सेवा अधिनियम जिसमें अधिकारियों के वेतनमान और अन्य पात्रतायें शामिल हैं स्केल-I से स्केल-VII तक के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, मौजूदा वार्ता में, इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन ने हमें सूचित किया है कि इस बार, अधिकारियों की वार्ता केवल स्केल-I से स्केल-III तक सीमित रहेगी। इस प्रकार, स्केल-IV से स्केल-VII के अधिकारियों को वार्ता तथा वेतन पुनरीक्षण से बाहर रखे जाने के प्रयास हैं। हम 15.9.2017 को हुई हमारी पिछली बैठक के दौरान इसे आपके संज्ञान में लाये थे। फिर भी आईबीए के दृष्टिकोण में कोई सुधार या बदलाव नहीं है।

हम इस मामले में आपके हस्तक्षेप तथा आगामी वेतन पुनरीक्षण में स्केल-I से स्केल-VII तक के सभी अधिकारियों को शामिल करने तथा जल्द से जल्द वार्ता सम्पन्न करने के लिए इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को सलाह देने का अनुरोध करते हैं।

सधन्यवाद,

आपके विश्वासपात्र,

ह0...
के.के. नायर, चेयरमैन

ह0...
संजीव के. बन्दलीश, संयोजक